

विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम



डॉ. सुमित श्योराण

सहायक प्रोफेसर, डीएवी कॉलेज
फॉर गर्ल्स, यमुनानगर (हरियाणा)

इस पाठ में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है। विभिन्न प्रावधान विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न योजनाएं पीडब्ल्यूडी के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन कर रही हैं। शिक्षार्थी द्वारा इस सामग्री की प्रभावी उपयोगिता का समर्थन करने के लिए मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए स्व-सिमुलेशन भी प्रदान किया जाता है। इससे शिक्षार्थी को मॉड्यूल में चर्चा की गई सामग्री के संबंध में शिक्षार्थी द्वारा विकसित समझ का शीघ्रता से मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इस सामग्री पर व्यापक ज्ञान आधार प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को इसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत की दशकीय जनसंख्या जनगणना के हिस्से के रूप में विकलांगों को प्रचारित करने के लिए 2001 से किए गए प्रयास, स्वतंत्रता के बाद की विसंगति को ठीक करना और विकलांग लोगों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने के कदम प्रमुख मील के पत्थर हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय में विकलांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। कानून में सन्निहित अधिकारों, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना सार्वजनिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने और विकलांगों के जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है।

भारत के पास विकलांगता के संबंध में नीति और अभ्यास का एक लंबा अनुभव है, जिसमें 1872

की शुरुआत से विकलांगता पर जनगणना की जानकारी एकत्र करना और 19वीं शताब्दी से संचालित विशेष स्कूल और संस्थान शामिल हैं। कई देशों की तरह, इसमें भी 1912 के भारतीय विकलांगता अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी और मंदबुद्धि लोगों के लिए विशिष्ट प्रावधान थे। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 41 में पीडब्ल्यूडी के लिए सामान्य राज्य दायित्वों को भी स्वीकार किया, और राज्य सूची में "विकलांगों और विकलांगों की राहत" के तहत बेरोजगार" इसके बाद, 1960 के दशक से रोजगार रियायतें जैसे विशिष्ट उपाय शुरू किए गए।

भारत में विकलांग व्यक्ति के कानूनी अधिकार:

भारत में विकासशील देशों की विकलांगता के लिए अधिक विकसित राष्ट्रीय नीति ढांचे में से

एक है, हालांकि विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि, सामाजिक नीति के कई क्षेत्रों की तरह, संस्थागत क्षमता और समन्वय की चुनौतियों ने कार्यान्वयन में योगदान दिया है जो अक्सर वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, भारत में विकलांग लोगों को उचित विचार और मान्यता दी जाती है। विकलांग व्यक्तियों को उनके मौलिक और बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिनियम, कानून और प्रावधान दिए गए। (i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987; (ii) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम); (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 और

2000 में संशोधित (आरसीआई अधिनियम); और (iv) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम) भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख अधिनियम और कानूनी ढांचे हैं। भारतीय संविधान में भी विकलांग व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

इन सामान्य लेखों के अलावा, ऐसे विशिष्ट कानून भी हैं जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनका प्रचार-प्रसार करते हैं, जिनकी व्याख्या नीचे दी गई है।

2.2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

यह अधिनियम 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकलांग लोगों के लिए समान अवसर और दिन-प्रतिदिन के जीवन में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। अधिनियम पुनर्वास के निवारक और प्रचारात्मक दोनों पहलुओं जैसे रोकथाम, शीघ्र हस्तक्षेप, शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों के लिए विशेष बीमा

योजना प्रदान करता है। गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घरों की व्यवस्था, आदि।

यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, विकलांग लोग यहां आवेदन कर सकते हैं:

- केंद्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और
- राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त।

2.3 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987

WHO के अनुमान के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि भारत में 130 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं।

अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था :

- निकट भविष्य में आबादी के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना।
- सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और समुदाय में स्वयं सहायता के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान अधिनियम में उल्लेखित किया गया था।

2.4 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारत में विकलांग व्यक्तियों को 100 से अधिक वर्षों से पुनर्वास सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं। हालाँकि, आरसीआई (RCI) की स्थापना से पहले, प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए क्षेत्र में शायद ही कोई योजनाबद्ध प्रयास किए गए थे। देश में पुनर्वास सेवाओं के विस्तार में उपयुक्त प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी प्रमुख बाधाओं में से एक रही है। भारत सरकार ने 1986 में एक पुनर्वास परिषद की स्थापना की और प्रमुख उद्देश्य था :

- प्रशिक्षण नीतियां और कार्यक्रम;
- विकलांग व्यक्तियों से निपटने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना
- इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करना;
- पुनर्वास पेशेवरों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना और
- पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना

आरसीआई एकमात्र संस्था है जो विकलांग व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन चक्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी शारीरिक और चिकित्सा पुनर्वास के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के जनशक्ति विकास का ख्याल रखती है; शैक्षिक पुनर्वास; व्यावसायिक पुनर्वास; और सामाजिक पुनर्वास।

2.5. ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999

केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह इस अधिनियम के अनुसार और विकलांगों के लाभ के लिए नई दिल्ली में ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित करे।

यह अधिनियम ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के गठन का प्रावधान करता है। ऐसी राष्ट्रीय संस्था एक ट्रस्ट होगी जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

□ विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से और यथासंभव पूरी तरह से उस समुदाय, जिससे वे संबंधित हैं, के भीतर और उसके करीब रहने में सक्षम और सशक्त बनाना।

□ विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवार के भीतर रहने के लिए

सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को मजबूत करना।

• विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठन को सहायता प्रदान करना।

□ विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं से निपटना जिनके पास परिवार का समर्थन नहीं है।

□ अपने माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में विकलांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना।

□ ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करना।

□ विकलांग व्यक्तियों के समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाना।

□ कोई अन्य कार्य करना, जो उपरोक्त वस्तुओं से आनुषंगिक हो।

3. विकलांगों के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं। कुछ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा नीचे दी गई है।

3.1. विकलांगता प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र

राज्य या जिला स्तर पर गठित संबंधित मेडिकल बोर्ड विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

प्रमाणित प्राधिकारी हैं। बोर्ड में जिले का एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उपविभागीय चिकित्सा अधिकारी और निर्दिष्ट क्षेत्र में एक अन्य विशेषज्ञ शामिल होता है, उदाहरण के लिए, दृश्य विकलांगता के मामले में एक नेत्र सर्जन; बोलने और सुनने की विकलांगता के मामले में या तो एक ईएनटी (ENT) सर्जन या एक ऑडियोलॉजिस्ट, लोकोमोटर विकलांगता के मामले में एक आर्थोपेडिक सर्जन या शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास में एक विशेषज्ञ और मानसिक विकलांगता के मामले में एक मनोचिकित्सक या एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक।

3.2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम

बड़े पैमाने पर समुदाय अक्सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमता से अनजान होता है। लोकप्रिय दिमाग में, विशेष जरूरतों को आमतौर पर बहुत कम अपेक्षाओं के साथ पहचाना जाता है। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। समावेशी शिक्षा जहां तक संभव हो उचित संशोधनों के साथ विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में नामांकित करने के विचार का समर्थन करती है। विशेषज्ञों की एक टीम (एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक और एक विशेष शिक्षक) द्वारा उनकी विकलांगताओं का आकलन करने के बाद, बच्चे को उचित शैक्षिक सेटिंग में रखा जाएगा। किसी भी

प्रकार की हल्की और मध्यम विकलांगता वाले बच्चों को गहन मूल्यांकन के बाद नियमित स्कूलों में, गंभीर विकलांगता वाले बच्चों को नियमित/विशेष स्कूलों में एकीकृत किया जा सकता है; जिन डॉपआउट्स को सामान्य स्कूलों का लाभ उठाने में समस्या होती है, वे ओपन स्कूलों में शामिल हो सकते हैं। खुले और विशेष विद्यालय विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

3.3. विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी योजना)

भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें से कई निम्न आय वर्ग से हैं। सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि विकलांग व्यक्तियों को न्यूनतम लागत पर सहायता/उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। सहायता/उपकरण प्रदान करने की आवश्यकता, जो विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद तेजी से फोकस में आ गई है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की मदद करना है उपयुक्त, वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक, मानक

सहायता और उपकरणों को अपनी पहुंच के भीतर लाकर।

3.4 विकलांगों का रोजगार

विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सहायता या तो सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष कक्षों के माध्यम से या शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध है। विशेष प्रकोष्ठों के मामले में 100% तक और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के विशेष रोजगार कार्यालयों के मामले में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.5. विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों और अन्य सुविधाओं का आरक्षण

भारत सरकार के आदेशानुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में ग्रेड 'सी' और 'डी' पदों पर 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत ऋण लेने के पात्र हैं, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

- लाभकारी व्यवसाय अपनाना चाहिए।
- सिंचित होने पर 1 एकड़ और असिंचित होने पर 25 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- एक ही समय में वित्त के दो स्रोतों के प्रति देनदारी नहीं होनी चाहिए।

□ बड़े पैमाने पर अपने दम पर काम करना चाहिए और ऐसी मदद के साथ जो उनके परिवार के अन्य सदस्य या कुछ संयुक्त भागीदार उन्हें दे सकते हैं और नियमित आधार पर वेतनभोगी नियोक्ताओं को नियुक्त नहीं करना चाहिए।

ऋण की राशि वित्तपोषित की जाने वाली प्रस्तावित विशेष योजना पर निर्भर करेगी। यह उधारकर्ता को अन्य स्रोतों से उधार लिए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्याज समान रूप से 4% प्रति वर्ष लिया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति डीआरआई योजना के तहत कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर आदि खरीदने के लिए ऋण के पात्र हैं, जो अधिकतम रु। 2500/- प्रति उधारकर्ता, बशर्ते ऐसी सहायता उत्पादक गतिविधियों और स्व-रोजगार उद्यमों के लिए अग्रिम राशि के साथ दी जाती है और डीआरआई योजना के तहत अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। "लघु उद्योगों के वित्तपोषण" की योजना के तहत 2500/- रुपये से अधिक और 2500 रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने वाले शारीरिक रूप से विकलांगों को ब्याज में रियायत देने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है।